www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 242 | जौनपुर बुधवार, 22 अप्रैल 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

राजस्थान की रिफाइनरी में आग के चलते स्थगित हुआ पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन का कार्यक्रम

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया है कि एचआरआरएल रिफाइनरी के क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (सीडीयू) के पास आग लगने की घटना के चलते आज 21 अप्रैल 2026 को होने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रिफाइनरी के उद्घाटन का कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में कहा कि इस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है और जरूरी सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। उद्घाटन के लिए नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। बताया जा रहा है कि सोमवार को राजस्थान के बाड़मेर जिले स्थित पचपदरा रिफाइनरी में अचानक आग लगने से मौके पर अफरा–तफरी मच गई। यह घटना उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले हुई, जिससे अधिकारियों में चिंता बढ़ गई, क्योंकि रिफाइनरी कार्यक्रम स्थल से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, आग बुझाने के लिए करीब 20 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। इमरजेंसी टीमों और रिफाइनरी के कर्मचारियों ने मिलकर इनबिल्ट सिस्टम की मदद से आग पर काबू पाया। पुलिस कंट्रोल रूम के अधिकारियों के मुताबिक, लगातार प्रयासों के बाद स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ गई।

मध्य पूर्व में तनाव के बीच 'वेट एंड वॉच' मोड में आरबीआई'

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि केंद्रीय बैंक मिडिल ईस्ट में तनाव पर करीब से नजर रख रहा है और भविष्य की ब्याज दरों को लेकर फिलहाल वह कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आपूर्ति में लंबे समय तक रुकावट रहने से भारत में व्यापक स्तर पर मुद्रास्फीति का खतरा है। अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय में अपने भाषण में मल्होत्रा ने कहा कि मौजूदा संघर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सीधा खतरा है, क्योंकि इस क्षेत्र की देश के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया भारत के निर्यात का लगभग छठा हिस्सा, आयात का पांचवा हिस्सा, कच्चे तेल के आयात का आधा हिस्सा, उर्वरक आयात का दो–पांचवां हिस्सा और भारत को आने वाली रेमिटेंस में लगभग दो–तिहाई का योगदान देता है। उन्होंने कहा, वास्तविक चिंता दूसरे दौर के प्रभावों को लेकर है। आर.बी.आई गवर्नर ने चेतावनी दी कि आपूर्ति में अचानक आई कमी, अगर जारी रही तो सामान्य मूल्यों में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालाँकि उन्होंने कहा कि आर.बी.आई ब्याज दरों को लेकर जल्दबाजी में नहीं है ।

राष्ट्रसेवा से ही बनेगा विकसित भारत : पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सिविल सेवा दिवस के मौके पर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सिविल सेवकों को शुभकामनाएं दीं और उनके काम की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह दिन सिर्फ एक औपचारिक अवसर नहीं है, बल्कि यह सुशासन और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ष्सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सभी सिविल सेवकों को मेरी शुभकामनाएं। यह सुशासन और राष्ट्र–निर्माण की दिशा में काम करने के हमारे संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करने का एक अवसर है। जमीनी स्तर से लेकर नीति–निर्माण तक, सिविल सेवकों के प्रयास अनगिनत लोगों के जीवन को स्पर्श करते हैं और भारत की प्रगति में अपना योगदान देते हैं। कामना है कि हमारे सिविल सेवक अपने कर्तव्य के सर्वोच्च मानकों को बनाए रखते हुए उत्कृष्टता, करुणा और नवाचार के साथ देश की सेवा करते रहें। एक अन्य पोस्ट में पीएम ने कहा, राष्ट्रसेवा ही विकसित भारत की नींव है। सिविल सेवा दिवस के गौरवशाली अवसर पर आइए, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर सशक्त, समृद्ध एवं संवेदनशील भारतवर्ष के निर्माण का संकल्प दोहराएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सिविल सेवा दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया, ष्सिविल सेवा दिवस के अवसर पर हमारे सिविल सेवकों को मेरी शुभकामनाएं। नीतियों को लागू करने, शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और पूरी ईमानदारी के साथ नागरिकों की सेवा करने के प्रति उनका समर्पण राष्ट्र–निर्माण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कामना है कि यह अवसर राष्ट्र–सेवा के प्रति उनके संकल्प को और अधिक दृढ़ करे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर कहा, ष्सिविल सेवा दिवस के पावन अवसर पर, मैं सभी सिविल सेवकों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जनसेवा के प्रति आपका समर्पण और जमीनी स्तर पर किए गए आपके अथक प्रयास लोगों के जीवन में वास्तव में एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं।

मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे धुआंधार प्रचार, भाजपा के पक्ष में मांगेंगे वोट

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को राज्य के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। 23 अप्रैल को होने वाले मतदान से ठीक पहले यह उनका तमिलनाडु का पहला चुनावी दौरा है। यह दौरा चुनावी प्रक्रिया के बेहद महत्वपूर्ण चरण में हो रहा है, क्योंकि 21 अप्रैल की शाम को ही आधिकारिक प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होना है, जबकि मतों की गिनती 4 मई को की जाएगी। अपने इस चुनावी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करेंगे और प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर उनमें जोश भरेंगे। भाजपा नेताओं ने

इस दौरे को राज्य के चुनिंदा हिस्सों में पार्टी की पैठ मजबूत करने के लिए अंतिम दौर के प्रयास के रूप में वर्णित किया है। तमिलनाडु का चुनावी मुकाबला इस बार काफी जटिल और बहुकोणीय है, जहां मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ द्रमुक गठबंधन सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहा है। उसे अन्नाद्रमुक गठबंधन से कड़ी चुनौती मिल रही है, जिसे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हासिल है। इसके अलावा नाम तमिझार कत्छी और तमिलगा वेत्री कड़गम जैसी ताकतें भी मैदान में हैं, जिससे मुकाबला और भी रोचक हो गया है।भाजपा ने अंतिम चरण में अपने अभियान को तेज कर दिया है और वरिष्ठ नेताओं को अलग–अलग राज्यों में तैनात किया है।

पश्चिम बंगाल में बदलाव की आहट, इस बार खिलेगा कमल : रेखा गुप्ता

कोलकाता, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। जैसे–जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों के बीच आरोप–प्रत्यारोप और बयानबाजी भी तेज हो गई है। इसी क्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिम बंगाल की स्थिति और वहां की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर कई तीखे बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि जैसे–जैसे मतदान का दिन करीब आ रहा है, उनका विश्वास और मजबूत होता जा रहा है कि बंगाल की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। उनका मानना है कि पिछले कई वर्षों से राज्य के लोग डर और भय के माहौल में जी रहे हैं और अब वे बदलाव चाहते हैं। रेखा गुप्ता ने यह दावा भी किया कि जनता इस बार बदलाव का मन बना चुकी है और वह एक नई शुरुआत की उम्मीद कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चुनाव परिणाम के बाद जो नया सवेरा आएगा, वह राज्य के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगा, जिसमें हर नागरिक के लिए सम्मान, सुरक्षा और विकास की भावना होगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी दृष्टि में भविष्य का बंगाल भयमुक्त और विकास आधारित शासन की ओर आगे बढ़ेगा। रेखा गुप्ता ने पश्चिम बंगाल की मौजूदा टीएमसी सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए।

जर्मनी की यात्रा पर रक्षा मंत्री, एआई-ड्रोन टेक्नोलॉजी समेत मुद्दों पर होगा मंथन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में भारत के राजदूत अजीत गुप्ते ने म्यूनिख हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। जर्मनी स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यह दौरा भारत–जर्मनी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें औद्योगिक सहयोग, सैन्य जुड़ाव और साइबर, एआई और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अपनी यात्रा के दौरान, राजनाथ सिंह अपने जर्मन समकक्ष बोरिस पिस्टोरियस और सरकार के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इन चर्चाओं का केंद्र बिंदु रक्षा

औद्योगिक सहयोग को बढ़ाना, सैन्य जुड़ाव का विस्तार करना और साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ड्रोन प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों में नए अवसरों की खोज करना होगा। इस यात्रा के दौरान दोनों रक्षा मंत्रियों की उपस्थिति में रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप और संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा अभियानों के प्रशिक्षण में सहयोग के लिए एक कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। यात्रा से पहले जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन समझौतों को रक्षा उपकरणों के संयुक्त विकास और सह–उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।यह दौरा चल रही रक्षा सहयोग पहलों की समीक्षा करने और दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच भी प्रदान करेगा। राजनाथ सिंह द्वारा भारत की श्मेक इन इंडियाश पहल के अनुरूप संयुक्त उद्यमों, प्रौद्योगिकी साझेदारियों और सह–उत्पादन परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन रक्षा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने की उम्मीद है। पिछले सात वर्षों में किसी भारतीय रक्षा मंत्री की जर्मनी की यह पहली यात्रा है, जो वर्तमान समय में इस सहयोग के महत्व को रेखांकित करती है।

महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को नहीं मिलेगी राहत : अमित शाह

दार्जिलिंग, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने दार्जिलिंग में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी के राज में माताओं बहनों पर जमकर अत्याचार हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि हमारे गोरखा बहनों–भाइयों पर इन्होंने सैकड़ों गलत केस किए हैं। 4 मई को परिणाम आएगा, 5 को भाजपा सरकार बनेगी और 31 जुलाई से पहले भाजपा सरकार सारे गोरखा बहनों–भाइयों पर दर्ज सभी केस वापस ले लेगी। टीएमसी ने ये फर्जी केस कर गोरखा आंदोलन को दबाया, ये सारे केस भाजपा समाप्त करेगी और आपको आंदोलन न करना पड़े, ऐसा समाधान भी लेकर आएगी। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में भाजपा सरकार बनते ही 6 महीने के भीतर हर गोरखा के चेहरे पर संतोष की हंसी हो, ऐसा समाधान हम निकालेंगे। कांग्रेस और टीएमसी ने दार्जिलिंग और गोरखाकृदोनों के साथ

अन्याय किया है। कमल फूल की सरकार बनते ही 6 महीनों के अंदर दशकों पुरानी गोरखा समस्या का गोरखा के हिसाब से समाधान करके दिखाएंगे, यह हमारा वादा है। गृहमंत्री ने कहा, ष्उत्तर बंगाल वालों, एक बार भाजपा सरकार बना दीजिए। तीन चुनावों से दार्जिलिंग तो कमल फूल पर वोट कर ही रहा है, लेकिन इस बार पूरा बंगाल तय कर बैठा है कि दीदी को हटाने का समय आ गया है। यह चुनाव दार्जिलिंग की पहाड़ियों से लेकर गंगासागर और कोलकाता तक हमारी माताओं–बहनों को सुरक्षित करने का चुनाव है। ममता के राज में ढेर सारी माताओं–बहनों पर अत्याचार हुआ है। संदेशखाली ने पूरे बंगाल को शर्मसार किया। भाजपा सरकार हर बलात्कारी को चुन–चुनकर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी। गृहमंत्री ने टीएमसी सरकार पर मदरसों को अधिक बजट देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनजातीय विकास के लिए पहाड़ों और उत्तर बंगाल के लिए ममता सरकार का बजट 2000 करोड़ रुपए है, जबकि मदरसों और मुसलमानों के लिए ममता सरकार का बजट 5700 करोड़ रुपए से अधिक है। गोरखा समस्याओं के समाधान के लिए गृह मंत्री बनने के बाद मैंने तीन बड़ी मीटिंग बुलाईं, लेकिन एक बार भी ममता सरकार की ओर से प्रतिनिधि नहीं आया।

सीएम पहले लोकसभा की बहस सुनें : संजय राउत

मुंबई, (एजेंसी)। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने बढ़ते ड्रग्स के मामलों को लेकर महाराष्ट्र सरकार की आलोचना निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा का श्उड़ता भाजपाश हो गया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ड्रग्स पकड़ा जा रहा है। मुंबई, पुणे और नागपुर सहित कुछ और जगहों पर ड्रग्स ही ड्रग्स है। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर संजय राउत ने कहा कि परिसीमन विधेयक मंजूर नहीं हुआ इसलिए मोर्चा निकाला जा रहा है। महिला आरक्षण विधेयक 2023 में मंजूर हुआ। राष्ट्रपति ने उस विधेयक पर हस्ताक्षर किया और भाजपा ने विधेयक का अध्यादेश निकालकर लागू करना शुरू कर दिया है तो कौन से महिला आरक्षण विधेयक को लेकर मोर्चा निकाला जा रहा है? संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री को सबसे पहले लोकसभा का डिबेट सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप (मुख्यमंत्री) डिबेट के लिए ऐसे व्यक्ति को लेकर आएं, जो हमारे लेवल का हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को बुलाइए। अरविंद केजरीवाल के केस से जुड़े मुद्दों पर संजय राउत ने कहा कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था का दुर्भाग्य है। उन्होंने कहा कि अगर आपको ऊपर मेरा विश्वास नहीं है, मैंने कुछ साक्ष्य दिए हैं कि विश्वास क्यों नहीं है?

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए। एनसीपी एसपी नेता सुप्रिया सुले ने पुणे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने कहा कि भाजपा जानती है कि यह विधेयक 2023 में ही पास हो चुका था। हमने इस विधेयक को पास कर दिया है। यह ढाई साल पहले हुआ था, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा रहा है। सुप्रिया सुले ने कहा कि रोहित पवार पहले दिन से ही श्मिशन मोडश में हैं।

पारदर्शी व्यवस्था के तहत किसानों का गेहूं हर हाल में खरीदा जाएगा : शिवराज चौहान

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को विदिशा संसदीय क्षेत्र की गेहूं खरीदी की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कहा है कि किसानों को किसी भी तरह की समस्या नहीं आना चाहिए और हर किसान का गेहूं हर हाल में खरीदा जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विदिशा संसदीय क्षेत्र में गेहूं उपार्जन व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में विदिशा, सांची, गंजबासौदा, बुधनी, भोजपुर, खातेगांव और इछावर समेत सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों के विधायक एवं संबंधित जिलों के कलेक्टर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। समीक्षा के दौरान केंद्रीय मंत्री चौहान ने खरीदी व्यवस्था को सुचारु और पारदर्शी बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों के साथ पूरा समन्वय करते हुए सभी खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। साथ ही बारदाने की उपलब्धता, स्लॉट बुकिंग प्रणाली और किसानों की सुविधा से जुड़े हर पहलू पर सतर्कता बरती जाए। किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा या परेशानी नहीं होनी चाहिए और उपार्जन प्रक्रिया को पूरी तरह व्यवस्थित, सरल और किसान हितैषी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जिन समस्याओं और कमियों की पहचान स्थानीय स्तर पर हो सकती है, उनके लिए अधिकारी और जनप्रतिनिधि अपने स्तर पर तत्काल समाधान सुनिश्चित करें।

अयोध्या में आधा दर्जन एएलएस एम्बुलेंस गंभीर रूप से ग्रसित रोगियों के लिए साबित हो रही संजीवनी

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या।वर्तमान समय में अयोध्या मे भी एएलएस एंबुलेंस सेवा गंभीर मरीजों के जीवन के लिए संजीवनी साबित हो रही रही है।इस बात की जानकारी देते हुए कंपनी के सहायक प्रबंधक सुमन समीर द्विवेदी ने बताया कि इस एएलएस एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी मेड केयर 365 के द्वारा संचालित की जा रही है।बताया कि पहले सड़क हादसों तथा अन्य गंभीर रूप से ग्रसित रोगी इलाज के लिए जब तक लखनऊ वाराणसी में हायर सेंटर पहुंचते कि इसके पहले ही इन रोगियों की मौत हो जाती थीजिसे गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016 में प्रदेश मे एएलएस निःशुल्क एंबुलेंस सेवा की शुरूआत किया।उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एएलएस एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी मेड केयर 365 के द्वारा संचालित की जा रही।बताया कि इस समय अयोध्या जिले में छह एएलएस एम्बुलेंस हैं।जिनमें से दो एम्बुलेंस दर्शन नगर स्थित ट्रॉमा सेंटर (मेडिकल कॉलेज) में तैनात हैं।जबकि दो अयोध्या जिला अस्पताल में और दो श्री राम अस्पताल अयोध्या में तैनात है। उन्होंने बताया कि इन एंबुलेंस के तैनाती के बाद से कई दर्जन गंभीर रूप से घायल मरीज को हायर सेंटर समय रहते ले जाया गया जहां पर उनको नई जिंदगी मिली। बताया कि देखा जाए यह एंबुलेंस भी एक चलता फिरता अत्याधुनिक उपकरणों से लैस अस्पताल ही है।बताया कि एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस एक चलती–फिरती आईसीयू होती है।जो गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर और जीवन रक्षक दवाओं से सुसज्जित होती है।इसमें प्रशिक्षित पैरामेडिक्स होते हैं जो अस्पताल पहुंचने तक हृदय या सांस संबंधी गंभीर मरीजों को उन्नत चिकित्सा सहायता प्रदान करते हैं। इसमें वेंटिलेटर, कार्डियक मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर,सिरिंज पंप और ऑक्सीजन सिलेंडर होते है।इसमें पैरामेडिक स्टाफ और डॉक्टर (आवश्यकतानुसार) होते हैं जो जीवन रक्षक प्रक्रियाएं कर सकते हैं।इस एंबुलेंस में दिल का दौरा, गंभीर दुर्घटना, सांस की तकलीफ, या कोमा जैसे मामलों में जब मरीज को तत्काल गहन देखभाल की आवश्यकता हो।ये एम्बुलेंस सामान्य एम्बुलेंस की तुलना में अधिक जटिल और गंभीर मरीजों के लिए है।

संपादकीय

पहल के पीछे के इरादे पर शक

विदेशी चंदे की भारत में क्या भूमिका रही है और इसका किस हद तक अवांछित उद्देश्यों के लिए उपयोग हुआ है, इस बारे में स्पष्टता बनाने की जरूरत है। बेहतर होगा कि केंद्र इस बारे में श्वेत पत्र जारी करे। संसद के चालू सत्र में विदेशी अनुदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) संशोधन विधेयक ना पारित कराने के केंद्र के एलान से इस बारे में टकराव फिलहाल टल गया है। केंद्र ने कहा कि केरल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने इस मुद्दे पर अनावश्यक विवाद खड़ा किया। वैसे, कहा यह भी जा सकता है कि इसी चुनाव के कारण विधेयक को फिलहाल टालने पर केंद्र इतनी आसानी से राजी हो गया। वरना, विवादित विधेयकों को बहुमत के जोर से पारित कराने का उसका रिकॉर्ड जग–जाहिर है। केरल में भाजपा की नजर भी ईसाई मतदाताओं पर हैय इसके बावजूद कि भाजपा और उसके सहमना संगठनों का लंबे समय से इल्जाम है कि ईसाई संस्थाएं विदेशी धन का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए करती हैं। और संभवतरू इसीलिए एफसीआरए के नियमों में बदलाव को ईसाइयों ने अपने खिलाफ माना है। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने इसे खतरनाक और चिंताजनक बताया है, जबकि केरल और अन्य राज्यों में चर्च समूहों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। बहरहाल, विदेशी चंदे को सिर्फ सांप्रदायिक संदर्भ में देखना सही नजरिया नहीं है। बेहतर होगा कि ऐसे चंदे की व्यापक भूमिका पर विचार– विमर्श किया जाए। विदेशी चंदे की भारत में क्या भूमिका रही है और इसका किस हद तक अवांछित उद्देश्यों के लिए उपयोग हुआ है, इस बारे में स्पष्टता बनाने की जरूरत है। बेहतर होता कि केंद्र इस बारे में श्वेत पत्र जारी करता। उससे इस बारे में ठोस समझ बनाने में मदद मिलती। ले किन वर्तमान सत्ताधारी पार्टी पर आरोप है कि वह महज कुछ हलकों के लिए चंदे के स्रोत रोकना चाहती है, जबकि अपने सहमना संगठनों के लिए वह इसका रास्ता खुला रखना चाहती है। इसलिए उसकी ये पहल विवादास्पद हो गई है। वरना, हर देश का यह संप्रभु अधिकार है कि वह अपने यहां धन या अन्य माध्यमों से विदेशी हस्तक्षेप को नियंत्रित और विनियमित करे। ऐसा निष्पक्ष रुख एवं अधिकतम सहमति के साथ किया जाए, तो विवाद की संभावना न्यूनतम रहेगी। जबकि पहल के पीछे के इरादे पर शक हो, तो बात बिगड़ जाती है। ऐसा ही इस मामले में हुआ है।

पश्चिम बंगाल के चुनाव में महिलाओं की होगी निर्णायक भूमिका

तीर्थंकर

'लक्ष्मी भंडार' महज एक आर्थिक हस्तक्षेप से कहीं ज्यादा है। यह एक सामाजिक–राजनीतिक पुनर्संतुलन का प्रयास है। इस योजना ने महिलाओं को, सिर्फ अपने लिंग के आधार पर ही, इस योजना का लाभार्थी बनने का अवसर प्रदान किया है। इसके परिणामस्वरूप, मतदान का अधिकार अब महिला मतदाताओं के लिए अपनी पहचान और अपनी बात को जोरदार ढंग से रखने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। बयानबाजी, नए गठजोड़ और आपसी आरोपों–प्रत्यारोपों के बीच, पश्चिम बंगाल की महिला मतदाताएं पिछले एक दशक में एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरी हैं, क्योंकि उनके फैसले अब सरकारों के भविष्य को तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस, जिसका पिछले 15 सालों से राज्य पर एकछत्र राज रहा है, ने इस चुनावी मुकाबले में सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा हैकुल मिलाकर, पिछली राज्य विधानसभा में टीएमसी की ओर से 41 महिला विधायकों ने प्रतिनिधित्व किया था। तेज–तर्रार नेता ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली इस राजनीतिक पार्टी ने देश भर की अन्य राजनीतिक पार्टियों की तुलना में ज्यादा महिलाओं को चुनाव में उतारा है। राजनीति यह विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 13.94 प्रतिशत है, जो कि देश भर की अन्य राज्य विधानसभाओं के 8 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। टीएमसी की बदौलत, महिला मतदाताएं अब चुनावी समीकरणों में सिर्फ एक सहायक भूमिका नहीं निभा रही हैं।चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में 3,76,00,611 महिला मतदाताएं हैं। आने वाले चुनावों में सभी उम्मीदवार इस वर्ग को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि वे राजनीतिक माहौल को अपने पक्ष में मोड़ सकें। टीएमसी सरकार की प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना, 'लक्ष्मी भंडार' ने लोगों की राजनीतिक निष्ठाओं और उनकी आर्थिक वास्तविकताओं को पूरी तरह से बदल दिया है। 2021 में शुरू की गई इस योजना के 2.2 करोड़ लाभार्थी हैं, और इस पर खर्च किए गए हजारों करोड़ रुपये की राशि ने टीएमसी को लगातार चुनावों में जबरदस्त राजनीतिक फायदा पहुंचाया है, जिससे विपक्षी दलों के लिए अपनी जगह बना पाना और भी मुश्किल हो गया है।इस योजना ने महिलाओं को, सिर्फ अपने लिंग के आधार पर ही, इस योजना का लाभार्थी बनने का अवसर प्रदान किया है। इसके परिणामस्वरूप, मतदान का अधिकार अब महिला मतदाताओं के लिए अपनी पहचान और अपनी बात को जोरदार ढंग से रखने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। आंकड़े खुद–ब–खुद अपनी कहानी बयां करते हैं। जहां टीएमसी ने 52 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, वहीं वामपंथी दलों ने 34 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया हैय जबकि 2026 के राज्य विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और भाजपा ने क्रमशरू 35 और 33 महिला उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि टीएमसी ने बड़ी संख्या में महिला मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की है। राज्य टीएमसी की महिला विंग की प्रमुख चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि महिला मतदाताओं के नाम हटाए जाने का मकसद उनकी पार्टी के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन राज्य में महिलाओं के लिए चलाई जा रही सामाजिक कल्याण योजनाएं ही टीएमसी के पक्ष में महिलाओं के वोटों में आए बदलाव का एकमात्र कारण नहीं हैं। पश्चिम बंगाल की महिला मतदाताएं लंबे समय से अपनी गहरी राजनीतिक समझ के लिए जानी जाती रही हैं। उनके फैसले लेने का तरीका पारिवारिक चर्चाओं, सामाजिक दायरों और आखिर में वोटिंग बूथ की एकांत जगह में सामने आता है। यह पूरी तरह से राजनीतिक होता है और राज्य तथा महिला नागरिकों के बीच बदलते आपसी तालमेल से तय होता है। लेकिन महिला मतदाताओं के समर्थन को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह न तो एक जैसा होता है और न ही इसका पहले से अंदाजा लगाया जा सकता है। लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, रूपाश्री जैसी महिलाओं पर केंद्रित कुछ सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों के वोट टीएमसी को ही मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये योजनाएं बस इस बात को पक्का करती हैं कि टीएमसी के राजनीतिक परिदृश्य में महिलाओं की मौजूदगी को सम्मान की नजर से देखा जाए। महिला मतदाताओं के एक बड़े हिस्से को अपने पाले में करने के लिए, चुनावी प्रचार के तरीके में एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। चुनाव प्रचार संभालने वालों को इस बात को

नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि कोलकाता की महिला मतदाताओं की प्राथमिकताएं, ग्रामीण इलाकों की महिलाओं की प्राथमिकताओं से अलग होंगी। इस विविधता को देखते हुए, महिलाओं से जुड़े मुद्दों को और भी बारीकी से समझने की जरूरत है। महिला मतदाताओं का यह समूह कई तरह के लोगों से मिलकर बना है, इसलिए उम्मीदवार और उनके चुनाव प्रचारकों को अपनी बात रखने से पहले इस बात को ध्यान में रखना होगा।रैलियां, गठबंधन और जोरदार चुनावी अभियान हर चुनाव का एक अहम हिस्सा होते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की महिला मतदाताओं को अपना मन बनाने में मदद करने के लिए, एक ज्यादा संवेदनशील और जवाबदेह रवैया अपनाना जरूरी हैय महिलाओं पर केंद्रित सामाजिक कल्याण योजनाओं के अलावा, सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवारों को टिकट देना भी टीएमसी की लैंगिक संवेदनशीलता को दिखाता है। महिला मतदाताएंकृया और भी साफ शब्दों में कहें तो उनमें से ज्यादातर महिलाएंकृ 'खामोश किंगमेकर' (सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली) होती हैं। कुछेक को छोडकर, ज्यादातर महिलाएं राजनीतिक मंच के सबसे शक्तिशाली मंच से अपनी बात नहीं रखतीं। हो सकता है कि उनकी आवाज सबसे ज्यादा सुनाई देने वाली आवाज न हो। लेकिन यह एक सच्चाई है कि ज्यादातर महिला मतदाताएं तृणमूल की मुखिया ममता बनर्जी के साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस करती हैं। यही वजह है ।

चुनाव आयोग की भूमिका पर संदेह और सवालों का घेरा

राजेश

एसआईआर की नई प्रक्रिया सामान्य लोगों के लिए कठिन है। एसएसआर में मौजूदा सूची में वोटरों के नाम जोड़े और काटे गए थे। लेकिन एसआईआर में सूचियां नए सिरे से बनी हैं। पहले पुनरीक्षण में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर–घर जाकर अपने रजिस्टर में मतदाताओं की संख्या और उनके ब्योरे की जांच करते थे। लेकिन एसआईआर के लिए अपूर्व तरीका अपनाया गया है। सभी वोटरों के लिए गणना फार्म भरने की समय सीमा एक माह तय की गई है। कुछ श्रेणी के वोटरों के लिए नागरिकता सहित कई अन्य दस्तावेज जमा करना जरूरी है। भारतीय संविधान की धारा 326 के अनुसार लोकसभा और हर राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और 18 वर्ष की आयु का है, उसे चुनाव में वोटर के बतौर दर्ज होने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट अपने कई फैसलों में इस अधिकार का जिक्र कर चुका है। लेकिन, इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए हो रहे चुनाव में लगभग 27 लाख वोटर मतदान नहीं कर पाएंगे। यह स्थिति असाधारण है। देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की अवधारणा पर गंभीर आघात है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत नई वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया ने कई सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी मतदान के संवैधानिक हक की रक्षा के लिए अब तक निर्णायक कदम नहीं उठा सका है।चुनाव आयोग ने हर साल और चुनाव पूर्व होने वाले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) की बजाय 27 अक्टूबर 2025 को बंगाल सहित 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर कराने की घोषणा की थी। पिछले साल बिहारमें विधानसभा चुनाव से सिर्फ पांच माह पहले एसआईआर कराने पर विवाद उठे थे। मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सर्वोच्च अदालत के कहने पर आयोग ने आधार कार्ड को पहचान के दस्तावेजों में शामिल करने सहित कुछ सुधार किए थे। कोर्ट ने चुनाव से पहले एसआईआर की विवादित प्रक्रिया को रोकने की जरूरत नहीं समझी थी। बंगाल के हालात तो बेहद चिंताजनक और विवादास्पद हैं।एसआईआर की नई प्रक्रिया सामान्य लोगों के लिए कठिन है। एसएसआर में मौजूदा सूची में वोटरों के नाम जोड़े और काटे गए थे। लेकिन एसआईआर में सूचियां नए सिरे से बनी हैं। पहले पुनरीक्षण में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर–घर जाकर अपने रजिस्टर में मतदाताओं की संख्या और उनके ब्योरे की जांच करते थे। लेकिन एसआईआर के लिए अपूर्व तरीका अपनाया गया है। सभी वोटरों के लिए गणना फार्म भरने की समय सीमा एक माह तय की गई है। कुछ श्रेणी के वोटरों के लिए नागरिकता सहित कई अन्य दस्तावेज जमा करना जरूरी है।बंगाल में दूसरे राज्यों से अलग हटकर प्रक्रिया अपनाई गई है। वहां तार्किक विसंगतियों के नाम पर प्रक्रिया को पेचीदा बना दिया है। यह बदलाव संदेह और सवालों का घेरा खड़ा करता है। चुनाव आयोग का मानना है कि जो वोटर नई सूची में इस वक्त नहीं हैं, उनका या तो 2002–03 की सूचियों से संबंध साबित नहीं हुआ है या उनके मामलों में कुछ तार्किक विसंगतियां हैं। तार्किक विसंगतियों को पांच कैटेगरी में बांटा गया है, इनमें नाम की वर्तनी में अंतर, माता–पिता और वोटर की आयु के बीच अंतर, एक ही परिवार या पूर्वज से जुड़े छह से अधिक लोग जैसे बिंदु शामिल हैं। नतीजतन कुछ परिवारों के कई सदस्य तो सूची में हैं जबकि कुछ बाहर कर दिए गए हैं। बंगाल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच की 13 अप्रैल को गई टिप्पणियों पर गौर करना जरूरी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व की खंडपीठ के जस्टिस जोयमाल्या बागची ने कहा कि ' जिस देश में आपका जन्म हुआ है,वहां वोटर लिस्ट में रहना और मताधिकार न केवल संवैधानिक बल्कि भावनात्मक भी है। एक लोकतांत्रिक सरकार चुनने की प्रक्रिया में आपकी हिस्सेदारी नागरिकता और राष्ट्रभक्ति की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। हमें इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि मूल एसआईआर में 2002 की सूचियों में शामिल लोगों की जांच का प्रावधान नहीं था। उन्होंने कहा कि यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में जीत का मार्जिन 2 फीसदी है और 10 फीसदी वोटर हटाए गए हैं तो हम ऐसे मामलों की जांच करेंगे'। कोर्ट ने उन वोटरों को मतदान की अनुमति दे दी है जिन्हें ट्रिब्यूनल की हरी झंडी मिल गई है। बहरहाल, उन 27 लाख वोटरों में से अधिकतर लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है जिनके नाम कटे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक 17 अप्रैल तक बंगाल की मतदाता सूचियों में एक भी नाम नहीं जुड़ा था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक कांग्रेस प्रत्याशी सहित दो लोगों के नाम जुड़े थे। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया में तमाम पेचीदगियों के बावजूद उसे सही ठहराया है। कोर्ट मानता है कि मूल एसआईआर में 2002 की सूचियों की जांच का प्रावधान नहीं था। फिर भी, उसे रोकने की जरूरत नहीं समझी गई है। इन सुझावों पर गौर नहीं किया गया है कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहां प्रक्रिया को चुनाव नतीजे आने तक स्थगित कर दिया जाए। सवाल है,अगर ऐसे राज्यों में कुछ माह बाद एसआईआर होती तो क्या फर्क पड़ जाता। आयोग इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है? 2002 की एसआईआर 12–13 माह में पूरी हुई थी। अब इस काम को पांच माह में निपटाने की क्या जरूरत है? आयोग ने एसआईआर की समयसीमा पर जताई गई तमाम आपत्तियों को नजरअंदाज किया है। उसने अपने अंदरूनी सिस्टम से आए सुझावों की अनदेखी की है। इंडियन एक्सप्रेस में 12 अप्रैल को प्रकाशित खबर के अनुसार महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) एस चोकलिंगम ने 25 नवंबर 2025 को आयोग को लिखे एक पत्र में कहा कि प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। वैसे, महाराष्ट्र उन 12 राज्यों में नहीं है जहां एसआईआर हुई है। आयोग ने एसआईआर पर राज्यों की राय मांगी थी। पत्र में उल्लेख है कि महाराष्ट्र में नवंबर 2001 से दिसंबर 2002 के बीच यह काम हुआ था। इसके पीछे वोटरों के नाम काटने का नहीं बल्कि सूची को संशोधित करने का आइडिया है। लिहाजा, इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समय दिया जाना चाहिए। पत्र में वोटरों के मौजूदा डेटा का पिछली एसआईआर के डेटा से मिलान करने पर भी सवाल उठाया है। लिखा है, इस काम में ज्यादा समय लगता है और यह चुनाव आयोग की गाइडलाइन में भी शामिल नहीं है। महाराष्ट्र के सीईओ का पत्र ही चुनाव आयोग की नीयत को जांच के दायरे में लाता है। लगता है, एसआईआर का मकसद वोटर लिस्ट को साफ–सुथरा बनाने की बजाय वोटरों के नाम काटने का है।

महिला आरक्षण,परिसीमन संविधान संशोधन बिल

अजय दीक्षित

लोकसभा सरकार द्वारा पेश महिला आरक्षण, परिसीमन संविधान संशोधन बिल पारित नहीं हो सका है क्योंकि सरकार दो तिहाई समर्थन नहीं जुटा सकी इसलिए 298 मत लाकर गिर गया। विपक्ष ने कोई सहयोग नहीं किया कांग्रेस,सपा, डीएमके, तुड़मूल कांग्रेस, बीजेडी, सीपीएम, सीपीई, क्रस्क्क, सहित डालो विरोध में 230 का अकड़ा जूता लिया जबकि सरकार को 336 मतों की आवश्यकता थी। इससे पहले लोकसभा में जमकर बहस हुई।बिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्तुत किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, निशिकांत दुबे, के सी वेणुगोपाल,आदि नेताओं ने भाग लिया। इस बिल के गिरने से सरकार अचरज में नहीं है उसे पहले ही मालूम था।इसी लिए उसने जो बिल का प्रारूप पेश किया वह महिला आरक्षण तो था ही था बल्कि सरकार की मनसा परिसीमन बिल की अधिक थी ।2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार आई है।12 वर्ष में सत्ता और विपक्ष में कटुता इतनी बढ़ गई है कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात भी नहीं होती है।जिस तरह से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, और अन्य कांग्रेस नेता आरोप लगा ते रहते हैं कि भारत लोकतांत्रिक संस्थाओं को हाइजैक कर लिया है। सर्वोच्च न्यायालय से लेकर चुनाव आयोग तक कांग्रेस ने निष्पक्षता के कटघरे खड़ा कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि श्वष्ठ, सीबीआई,ह्नष्टक्रञ्जश्व,ह्वद्ध्र, आदि को भी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्यों के विधानसभा चुनाव में आयोग की भूमिका को संदेहास्पद मानती है यहां तक कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला,चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी महायोग का नोटिस दिया जा चुका है। अन्य पार्टियां जैसे तुड़मूल कांग्रेस, बीजेडी, सीपीएम, सीपीई, क्रस्क्क, सपा, डीएमके, भारतीय जनता पार्टी को दुश्मन मानती है। परिसीमन बिल में मुख्य अपत्ति यह थी सरकार कैसे तय कर रही है क्योंकि यह तो चुनाव आयोग या परिसीमन आयोग को निर्णय करना चाहिए वह भी काफी एक्सरसाइज के बाद जबकि बिल में लिखा गया लोकसभा संख्या 850 होगी जिसमें से 35 यूनियन टेरोटरी के लिए आरक्षित होंगी।बिल राज्य बार पचास फीसदी सीट लोकसभा में बढ़ाने का प्रस्ताव था इसी प्रकार राज्यों की विधानसभा सीटों बढ़ेगी। हालांकि दक्षिण भारत के राज्यों में 129 के बजाय 195 सीट का प्रस्ताव था आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, में 24 फीसदी सीट तय की गई जो वर्तमान से कुछ ही अधिक है। लेकिन विपक्ष की आपत्ति उत्तर प्रदेश में 120, महाराष्ट्र में 78, मध्य प्रदेश में 59,इसी प्रकार राजस्थान, दिल्ली, बिहार, गुजरात, हरियाणा,को लेकर थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सदन में कह दिया कि हम इस बिल विरोध करेंगे चाहे ह्रष्ठ किसी महिला तो ही प्रधानमंत्री बना दे । राहुल गांधी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही यह कह कर भाषण दिया कि महिला आरक्षण तो बहाना है असली बात तो परिसीमन की है। लेकिन प्रस्ताव कोई कमी नहीं थी । कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से कोई उम्मीद नहीं रखे। कांग्रेस और अन्य पार्टियां की पीड़ा है कि अब गिने चुने राज्य रहगये है जहां सरकार अन्य पार्टियां की है जिनमें झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, कर्नाटक, ही है। ये पहला मौका जब विपक्ष एक जुट हुआ है क्योंकि 12 वर्ष में मोदी सरकार ने कभी भी लोकसभा या राज्यसभा में बिल गिरने नहीं दिया है यहां तक कि जम्मू कश्मीर से संविधान की अनुच्छेद 370 पर भी सरकार हारी नहीं थी चाहे वह जीएसटी का मामला हो। 12 वर्ष जिस तरह मोदी सरकार ने कार्य ही नहीं किया बल्कि राज्य विधानसभा चुनाव में दो बार उत्तर प्रदेश,तीन बार बिहार,तीन बार मध्यप्रदेश,दो बार राजस्थान,तीन बार गुजरात,तीन बार हरियाणा,तीन बार उत्तराखंड,दो बार छत्तीसगढ़, ओडिशा,दो बार महाराष्ट्र,सहित 75 चुनाव जीते हैं बस यही कसक कांग्रेस को खाए जा रही है। सपा, डीएमके, तुड़मूल कांग्रेस, बीजेडी, सीपीएम, सीपीई,भी इसी कसक में जले भुजे जा रहे हैं।

भाजपा के हाथ कानून की तरह लंबे

अजीत द्विवेदी

हर दो साल पर होने वाले राज्यसभा चुनाव में आम लोगों की तो कम लेकिन राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों की बड़ी रूचि होती है। कौन उम्मीदवार होगा से लेकर कौन जीतेगा तक सारी चीजें बहुत दिलचस्प होती हैं। सबसे ज्यादा रोचक मामला विधायकों के वोट डालने का होता है। माननीय विधायक इसमें मतदाता होते हैं। यानी जिन लोगों को कई लाख लोग वोट देकर चुनते हैं वे राज्यसभा का सांसद चुनते हैं और सोचें, उनके भी वोट गलत तरीके से डाले जाने की वजह से अवैध हो जाते हैं! क्या यह बात किसी के गले उतरती है कि कोई विधायक ठीक ढंग से वोट नहीं डाल पाएगा? जाहिर है वह जान बूझकर अपना वोट अवैध कराता है। फिर सवाल है कि ऐसे नाटक की क्या जरुरत है? इसमें एक पहलू यह भी है कि राज्यसभा चुनाव में वोट अवैध होने या क्रॉस वोटिंग करने की घटनाएं प्रत्यक्ष रूप से भाजपा के शक्तिशाली होते जाने के समानुपातिक हैं। यानी जैसे जैसे भाजपा मजबूत हो रही है वैसे वैसे राज्यसभा चुनाव में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। राज्यसभा का चुनाव सांस्थायिक भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनता जा रहा है। बहरहाल, 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव के बाद जो सबसे अपरिहार्य आवश्यकता दिख रही है वह ये है कि राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के तरीके में बदलाव किया जाए। हर चुनाव में भाजपा जो करती है वह अलग है। उसे तो नहीं रोका जा सकता है। वह तो साम, दाम, दंड और भेद चारों तरीकों का इस्तेमाल करती रहेगी। भाजपा के शक्तिशाली होने के पहले जब कांग्रेस का दौर था, तब भी थोड़ी बहुत गड़बड़ होती थी। लेकिन अब वह गड़बड़ी कई गुना बढ़ गई है। अगर एक रूपक के हिसाब से कहें तो कांग्रेस के पास ओवरकोट होता था, वह कहीं से एकाध बटन लगाने का बंदोबस्त करती थी। अब भाजपा के पास एक बटन भी होता है तो वह ओवरकोट का इंतजाम कर लेती है। यानी जीतने के लिए 30 वोट की जरुरत है और भाजपा के पास तीन वोट हैं तो वह चुनाव लड़ सकती है और जीत भी सकती है। सो, इसका तो कोई उपाय नही हो सकता है। इसी सचाई के बीच पार्टियों को सर्वाइवल के उपाय करने होंगे। हां, अगर चुनाव आयोग वोटिंग के नियम भी बदल दे तो कई तरह की नौटकियों से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी नौटकियों से जिसकी किसी सभ्य लोकतांत्रिक समाज में जगह नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कुछ नहीं करना है। वोटिंग के तरीके को सरल बना दिया जाए। इसमें सबसे पहला बदलाव तो यह करने की जरुरत है कि अगर राज्यसभा का चुनाव ओपन बैलेट से होता है और चुनाव में दलबदल का कानून लागू नहीं होता है तो इसे पूरी तरह से ओपन कर देना चाहिए। इस नौटंकी का कोई मतलब नहीं है कि ओपन बैलेट से वोट करेंगे लेकिन वोट सिर्फ अपनी पार्टी के पोलिंग एजेंट को दिखाएंगे। अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने देख लिया तो वोट अवैध हो जाएगा। क्यों भाई, दूसरे ने देख लिया तो क्यों अवैध हो जाएगा? जब वह विधायक किसी को भी वोट दे, उसके खिलाफ दलबदल कानून नहीं लागू होना है तो उसका वोट कोई भी देख ले, उससे क्या फर्क पड़ता है? सोचें, पार्टी के पोलिंग एजेंट को पता है कि उसकी पार्टी का विधायक है तो वह पार्टी के उम्मीदवार को वोट करेगा। अगर वह पार्टी उम्मीदवार को वोट नहीं करेगा यानी क्रॉस वोटिंग करेगा तब भी पोलिंग एजेंट को उसे अपना वोट दिखाना ही है। वह जिसके पक्ष में क्रॉस वोटिंग करेगा उसको पहले से पता होगा कि क्या होने वाला है। और क्रॉस वोटिंग के बावजूद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। फिर भी यह नौटंकी चलती है कि अगर दूसरा व्यक्ति वोट देख लेगा तो वोट अवैध हो जाएगा। इसका सीधा समाधान तो यह है कि राज्यसभा चुनाव में ओपन बैलेट हो, विधायक बता कर वोट करें कि वे किसको वोट दे रहे हैं और वोट अवैध करने की व्यवस्था ही समाप्त हो। या तो वोट अवैध करने की व्यवस्था समाप्त हो या फिर क्रॉस वोटिंग करने पर दलबदल कानून लागू करने का प्रावधान किया जाए। इससे राज्यसभा चुनाव में होने वाले बेहिसाब भ्रष्टाचार कुछ कम होगा। इसी तरह की एक नौटंकी यह है कि एक खास तरह के पेन से ही वोट देना होगा। अगर पेन बदल गया या स्याही बदल गई तो वोट अवैध हो जाएगा। हरियाणा में कुछ साल पहले ऐसा ही हुआ था। जब पेन बदलने से कांग्रेस के 14 में से 13 विधायकों का वोट अवैध हो गया था। इस वजह से इनेलो व कांग्रेस के साझा उम्मीदवार आरके आनंद चुनाव हार गए थे। सवाल है कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था में मतदान होता है और बैलेट पर अपनी प्राथमिकता लिख कर विधायक अपना वोट बक्से में डालते हैं, जो सबके सामने होता है और सबके सामने खुलता है तो फिर उसमें क्या गड़बड़ी हो सकती है, जिसे रोकने के लिए पेन और स्याही की ऐसी व्यवस्था बनाई गई है? पहले ठप्पा लगाने की व्यवस्था थी। उसे बहाल किया जाए और वोटिंग के समय ठप्पा थोड़ा इधर उधर या ऊपर नीचे हो जाने के आधार पर वोट अवैध न किया जाए। सोचें, कैसे कैसे कारण से वोट अवैध हो जाते हैं। इस बार हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में एक विधायक का वोट इसलिए अवैध हो गया क्योंकि उसने पहली प्राथमिकता का वोट देने के लिए अंक में 1 लिखने के बाद उसके आगे डॉट लगा दिया था। ऐसी ही छोटी छोटी बातों पर पहले भी वोट अवैध होते रहे हैं। जैसे किसी ने प्राथमिकता स्पष्ट रूप से नहीं लिखी या किसी ने लिखी तो नंबर ऊपर या नीचे हो गया या किसी ने अपने पोलिंग एजेंट को वोट दिखाया तो दूसरे ने भी देख लिया आदि आदि। इसलिए ऐसी बातों की बजाय चुनाव की बिल्कुल सरल व्यवस्था बनानी चाहिए। राज्यसभा में मतदाता गिनती के होते हैं। सामने टेबल लगा कर सभी पार्टियों के पोलिंग एजेंट बैठें और वोट देने आए विधायक से पूछ लिया जाए कि वह किसको वोट कर रहा है और उस उम्मीदवार के आगे उसका नाम दर्ज कर दिया जाए। न कोई झंझट है और न वोट अवैध होने की चिंता है। कहा जाता है कि दलबदल कानून इसलिए नहीं लगाया जाता है ताकि विधायक अंतरात्मा की आवाज पर वोट कर सकें। सबको पता है कि अंतरात्मा हमेशा पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ वोट करने के लिए प्रेरित करती है क्योंकि अंतरात्मा पार्टी के प्रति निष्ठा से ज्यादा दूसरी चीजों से प्रभावित होती है। फिर भी सवाल है कि जब अंतरात्मा की आवाज पर वोट करना है तो छिपाना क्या है?

जौनपुर में मौसम बदलते ही बढ़ीं बीमारियां, जिला अस्पताल की ओपीडी में उमड़ी भीड़

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर में मौसम के तेजी से बदलते मिजाज के साथ ही मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तेज धूप और गर्मी के कारण डायरिया, उल्टी–दस्त, बुखार और अन्य संक्रमण तेजी से फैल रहे हैं, जिससे मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसका सीधा असर अमर शहीद उमानाथ सिंह जिला अस्पताल की ओपीडी पर देखा जा रहा है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। पर्चा बनवाने के लिए लोगों को लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. अशोक कुमार यादव ने बताया कि अचानक मौसम परिवर्तन और खानपान में लापरवाही के कारण मौसमी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। उन्होंने बताया कि इन दिनों पेट में संक्रमण, डायरिया, हीट

स्ट्रोक, सिर दर्द, घबराहट, बेचैनी, गला सूखना, तेज बुखार और दिमागी बुखार जैसी समस्याओं के मरीज अधिक संख्या में अस्पताल आ रहे हैं। सभी मरीजों का समुचित उपचार किया जा रहा है। डॉ. यादव ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा कि गर्मी के मौसम में तला–भुना और मसालेदार भोजन कम करें तथा अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बेहद जरूरी है। इसके अलावा तेज धूप में निकलते समय सिर को गमछे या हेलमेट से ढककर रखें, जिससे लू से बचाव किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि शादी–विवाह के इस मौसम में लोग अधिक तेल–मसाले वाले भोजन का सेवन कर रहे हैं, जिससे पेट संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं, इसलिए इस पर नियंत्रण जरूरी है। वहीं, चीफ फार्मासिस्ट आशुतोष पाठक ने बताया कि जिला अस्पताल में प्रतिदिन लगभग 1500 मरीजों का पंजीकरण हो रहा है, जिनमें ज्यादातर डायरिया, उल्टी–दस्त और बुखार के मरीज शामिल हैं। इमरजेंसी में भी मरीजों का तत्काल उपचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता है और सभी मरीजों को आवश्यक उपचार मुहैया कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी लक्षण के दिखने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की है।

बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा, नामांकन और गुणवत्ता सुधार पर जोर

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर, 22 अप्रैल। मंडलीय शिक्षा निदेशक (बेसिक), वाराणसी मंडल के निर्देशन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) हेमंत राव ने की। बैठक में विभागीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए हेमंत राव ने अधिकारियों को

निर्देशित किया कि स्कूल चलो अभियान के तहत शत–प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान कर उन्हें पुनः विद्यालय से जोड़ने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। निपुण भारत अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण गुणवत्ता में सुधार तथा

आवश्यक जन सूचना (पब्लिक नोटिस)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ASRDEEP GROUP OF COMPANIE S,, (एक कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 1956 / 2013 के तहत पंजीकृत है), का पंजीकृत कार्यालय द्वारका, नई दिल्ली, स्थित है।

हमें विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी मिली है कि कुछ असामाजिक तत्व / अनधिकृत व्यक्ति / एजेंट ललित कुमार दीपक (लखनऊ), दुर्गेश दुबे (मुंबई), कमल सोनी (लखनऊ), मंगल दुबे (मुंबई / नासिक) के नाम पर, हमारी कंपनी के ब्रांड एंबेसेडर, मार्केटिंग हेड बन कर, फर्जी ऑफिस खोलकर, फर्जी लेटरहेड, ईमेल आईडी या दस्तावेजों का उपयोग करके, जनता को ब्रांड एंबेसेडर बनाने के नाम पे और कंपनी से सुविधा दिलाने के नाम पे, निवेश करने, या अन्य बहाने से पैसे की अवैध मांग कर रहे हैं। कम्पनी के संज्ञान में आने पर जनहित में यह स्पष्ट किया जाता है कि ASRDEEP GROUP ने किसी भी व्यक्ति या एजेंसी को सार्वजनिक रूप से पैसे इकट्ठा करने के लिए अधिकृत (Authorize) नहीं किया है। अगर कोई ऐसी बात करता है तो वो झूठ बोल रहा है।

हमारी कंपनी किसी भी नकद लेनदेन (Cash Transaction) को प्रोत्साहित नहीं करती है। सभी भुगतान केवल कंपनी के आधिकारिक बैंक खाते में ही स्वीकार किए जाते हैं।

यदि ये व्यक्ति, कंपनी के कर्मचारी होने का दावा करता है, तो कृपया उसे भुगतान करने से पहले आधिकारिक कार्यालय नंबर Call: 8858–044–270, या ईमेल ईमेल आईडी – info@asrdeepgroup.com, पर सत्यापन (Verify) अवश्य करें।

अनधिकृत व्यक्तियों को किए गए किसी भी भुगतान के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। जनता को सलाह दी जाती है कि ऐसे धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहें। यदि कोई व्यक्ति ऐसी मांग करता है, तो कृपया तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन या हमारी कंपनी को सूचित करें।

Legal Department
(ASRDEEP GROUP)
दिनांक – 21–04–2026
स्थान– नई दिल्ली

जबरन स्मार्ट मीटर लगाकर जनता को लूट रही है भाजपा सरकार- डा. प्रमोद कुमार सिंह

प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेसियो ने बिजली विभाग पर किया धरना–प्रदर्शन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी चौराहे से हाइडिल तक पैदल मार्च निकाला और बिजली विभाग के खिलाफ धरना–प्रदर्शन कर विरोध जताया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। धरना को संबोधित करते हुए डॉ. प्रमोद कुमार सिंह ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना जनता की सहमति के जबरन स्मार्ट मीटर लगाकर उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक ओर बिजली कटौती से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर प्रीपेड मीटर के कारण बढ़े हुए बिल से आम जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। उन्होंने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने और जनता की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। डॉ. सिंह ने मांग की कि वर्तमान मीटर व्यवस्था को ही जारी रखा जाए और जबरन प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को जनता के हित में पारदर्शी नीति अपनानी चाहिए। वहीं, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आरिफ खान ने कहा कि प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को लेकर जनता में आक्रोश और भय दोनों व्याप्त है। उन्होंने मांग की कि स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को पूरी तरह निरस्त किया जाए और इसके लिए गठित जांच समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। साथ ही अब तक उपभोक्ताओं से वसूले गए अतिरिक्त बिजली बिल को वापस किया जाए। प्रदर्शन के अंत में कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल के नाम संबोधित पांच सूत्रीय ज्ञापन अधिशासी अभियंता की अनुपस्थित में मेहदी बाबू को सौंपा। इस मौके पर डॉ. राकेश मिश्र, विनय तिवारी, लाल प्रकाश पाल, शिव मिश्रा, इरशाद खान, राजकुमारी मिश्रा, विजय प्रकाश वर्मा, जयप्रकाश मिश्रा, प्रवेश निषाद, इकबाल हुसैन, शमसुद जोहा, शाकिब अली, मुहम्मद असरफ सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन संगठन प्रभारी राकेश मिश्रा ने किया।

समाजवादी मजदूर सभा का प्रदर्शन, राज्यपाल को संबोधित सौंपा ज्ञापन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में बुधवार को समाजवादी मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपकर नोएडा में चल रहे श्रमिक आंदोलन पर कथित दमन रोकने और कानून का राज स्थापित करने की मांग उठाई। कार्यक्रम का नेतृत्व संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अमित यादव ने किया। ज्ञापन में कहा गया कि शासन–प्रशासन और औद्योगिक प्रबंधन की नीतियों के कारण श्रमिकों का शोषण बढ़ता जा रहा है, जिससे नोएडा में स्वतःस्फूर्त श्रमिक आंदोलन शुरू हुआ। इसके बाद सरकार ने मजदूरों के वेतन में आंशिक वृद्धि का निर्णय लिया, जिसकी अधिसूचना राज्यपाल के हस्ताक्षर से जारी की जा चुकी है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका समुचित लाभ श्रमिकों को नहीं मिल रहा है। अमित यादव ने कहा कि पिछले दो दशकों से बड़े पूंजी घरानों के हित में श्रमिकों की स्थिति लगातार खराब होती गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रमिकों से कम मजदूरी पर स्थायी प्रकृति के कार्य गैर–कानूनी ढंग से कराए जा रहे हैं। साथ ही, लंबे संघर्ष के बाद हासिल 8 घंटे कार्य दिवस की व्यवस्था को समाप्त कर कई स्थानों पर 12 घंटे तक काम कराया जा रहा है और साप्ताहिक अवकाश भी नहीं दिया जा रहा।

ज्ञापन में यह भी कहा गया कि वर्तमान महंगाई के दौर में श्रमिकों की आय उनके परिवार के भरण–पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है। संगठन ने नए श्रम संहिताओं (लेबर कोड) पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इनके जरिए श्रमिकों के पूर्व में प्राप्त अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। 'फ्लोर लेवल वेज' लागू कर न्यूनतम मजदूरी के अधिकार को प्रभावित किया जा रहा है।

कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल से मांग की कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए और नोएडा आंदोलन में हो रहे कथित दमन को तत्काल रोका जाए। इस दौरान अजय यादव, प्रदीप यादव, अखिलेश यादव, रमाशंकर चौहान, धीरज बिंद सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पुरानी रंजिश में युवक की लाठी–डंडों से पीटकर हत्या

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में बक्शा थाना क्षेत्र के टिकरी बभनौटी गांव में मंगलवार रात पुरानी रंजिश और जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में 45 वर्षीय अशोक मिश्रा की लाठी–डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई, जबकि करीब दस लोग घायल हो गए। घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। मृतक अशोक मिश्रा का अपने चाचा कमलाकांत मिश्रा से जमीन और मकान को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। पूर्व में भी दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो चुकी थी, जिसके बाद अशोक अपने परिवार के साथ कलीचाबाद में रहने लगे थे। वह नईगंज में आयुर्वेदिक दवा की दुकान चलाते थे और क्षेत्र में वैद्य के रूप में पहचान रखते थे। मंगलवार रात करीब साढ़े दस बजे अशोक अपने कुछ साथियों के साथ गांव पहुंचे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर चाचा पक्ष से विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी–डंडे चलने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हालात बिगड़ते देख अशोक के साथ आए कई लोग मौके से भाग निकले। इसके बाद हमलावरों ने अशोक को बांधकर बेरहमी से पीटा। उनके साथ आए अंकित मिश्रा निवासी नईगंज थाना लाइनबाजार को भी बांधकर मारपीट की गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौपेड़वा भेजा गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान देर रात अशोक मिश्रा की मौत हो गई। वहीं, सुनील मिश्रा, मृदुल मिश्रा और अंकित मिश्रा को गंभीर हालत में बीएचयू वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है।इस संबंध में बुधवार को जानकारी लेने पर थानाध्यक्ष विक्रम लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मृतक के भाई की तहरीर पर आठ नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात है।

साईं बाबा मंदिर का 30 वा स्थापना दिवस 24 अप्रैल शुक्रवार को

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हुसैनाबाद तिलकधारी महाविद्यालय के बगल स्थित साईं बाबा मंदिर का 30 वा स्थापना दिवस 24 अप्रैल शुक्रवार को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ साईं बाबा मंदिर में विधिवत आरती के उपरांत शुरू होगा। मंदिर के पुजारी पंकज पांडे , एवं लोलारकनाथ पाठक जी द्वारा बाबा की आरती कराई जाएगी।इस दौरान बाबा की पालकी के साथ हाथी घोड़े रथ बैंड बाजों के साथ बाबा की पालकी निकाली जाएगी। मंदिर के प्रबंधक संजय सिंह ने ये जानकारी देते हुए जनपद के समस्त लोगों से भंडारे में उपस्थित होने की अपील किया है।उक्त जानकारी मंदिर के प्रबंधक संजय सिंह एवं (निरीक्षक)इंद्रभान सिंह इंदु जी, एडवोकेट दुष्यन्त सिंह राजन गुप्ता ,और रमेश माली और मीडिया प्रभारी दीपक श्रीवास्तव द्वारा दिया गया।

मूल्यों और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़कर ही लोकतंत्र होगा समावेशी : प्रो. वंदना सिंह

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रायोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का भव्य शुभारंभ बुधवार को राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय, सिंगरामऊ में हुआ। राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित इस सेमिनार का विषय 'भारत में लोकतांत्रिक समावेशिता के 75 वर्ष' रहा। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. वंदना सिंह ने कहा कि लोकतांत्रिक समावेशिता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समाज को अपने मूल्यों और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब नई पीढ़ी नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक वातावरण को आत्मसात करे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. अरुण कुमार सिंह ने की।सेमिनार के मुख्य वक्ता आर्य कन्या पीजी महाविद्यालय, वाराणसी के प्रो. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक 'वेल्थ ऑफ नेशन्स' का संदर्भ देते हुए वर्तमान वैश्विक आर्थिक असमानता पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विश्व की लगभग 90 प्रतिशत संपत्ति केवल एक प्रतिशत लोगों के पास केंद्रित है, जो समावेशी लोकतंत्र के लिए चुनौती है। विशिष्ट अतिथि लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. आर.के. मिश्र ने कहा कि लोकतांत्रिक समावेशिता तभी सार्थक होगी जब स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगे। आयोजन सचिव प्रो. जय कुमार मिश्र ने विषय प्रवर्तन करते हुए कहा कि समावेशिता ही लोकतंत्र की वास्तविक पहचान है। कार्यक्रम का संचालन सहायक आचार्य डॉ. राजेश कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर प्रो. इंदु प्रकाश, डॉ. योगेश कुमार, डॉ. जे.पी. सिंह, डॉ. बृजेश प्रताप सिंह, डॉ. मनोज कुमार सिंह, डॉ. गिरीश मणि त्रिपाठी, डॉ. राजीव त्रिपाठी सहित अनेक प्राध्यापकों ने अतिथियों का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में प्रो. चंद्रलेखा, प्राचार्यगण प्रो. सुरेश कुमार पाठक, प्रो. सुधाकर सिंह, प्रो. शम्भू राम, प्रो. अखिलेश्वर शुक्ला, प्रो. पंकज सिंह, डॉ.दिग्विजय सिंह राठौर, डॉ. संजय सिंह, डॉ. अजय कुमार दुबे सहित बड़ी संख्या में शोधार्थी एवं छात्र–छात्राएं उपस्थित रहे।

वैश्विक स्तर पर ताप वृद्धि चिंता का विषय : प्रो. प्रमोद यादव

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में पृथ्वी दिवस के अवसर पर बुधवार को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के रज्जू भैया संस्थान में "ग्लोबल वार्मिंगरू वन प्लेनेट, वन चांस" विषय पर एक प्रभावशाली व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भू एवं ग्रहीय विज्ञान विभाग एवं 'सस्टेनेबिलिटी कमेटी' के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं संस्थान के निदेशक प्रो. प्रमोद कुमार यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि पृथ्वी दिवस हमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। उन्होंने बढ़ती वैश्विक तापवृद्धि, प्रदूषण एवं प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि समय रहते हम सचेत नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने विद्यार्थियों से ऊर्जा संरक्षण, वृक्षारोपण तथा सतत जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया। भू एवं ग्रहीय विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. नीरज अवस्थी ने कहा कि ग्रीनहाउस प्रभाव एवं ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व स्तर की गंभीर चुनौती बन चुके हैं। उन्होंने बताया कि बढ़ते तापमान के कारण हिमनदों का तेजी से पिघलना, समुद्र स्तर में वृद्धि एवं मौसम चक्र में असामान्य बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस एवं व्यावहारिक कदम उठाने हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान ग्लोबल वार्मिंग विषय पर एक जागरूकता वीडियो डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की गई, जिसने उपस्थित छात्रों एवं शोधार्थियों को गहराई से प्रभावित किया। सभी प्रतिभागियों ने जल संरक्षण, प्लास्टिक उपयोग में कमी, हरित परिसर निर्माण एवं सामूहिक जागरूकता अभियान चलाने पर बल दिया। अंत में विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने एवं पृथ्वी को सुरक्षित बनाने हेतु सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया। इस अवसर पर डॉ. धीरेन्द्र चौधरी, डॉ. श्याम कन्हैया सहित संस्थान के अन्य शिक्षकगण, शोधार्थी एवं छात्र–छात्राएं उपस्थित रहे।

शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुआ रुद्राभिषेक

आयोजक मंडल की ओर से पीपीसी के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम एवं प्रदेश सलाहकार सचिव कृष्णा पाठक का भी हुआ सम्मान

वाराणसी। जिले के सेवापुरी विकासखंड क्षेत्र के करधना ष्पाहीष स्थित नवनिर्मित शिव मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतिम दिवस यानी बुधवार को रुद्राभिषेक के साथ भंडारे के आयोजन से समापन अत्यंत श्रद्धा और भव्यता के साथ हुआ। इस अवसर पर आयोजक मंडल द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान दैनिक परफेक्ट मिशन के कार्यकारी संपादक एवं पत्रकार प्रेस क्लब के संस्थापकध्प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम पाठक को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। श्री पाठक के साथ ही पत्रकार प्रेस क्लब के प्रदेश सलाहकार सचिव कृष्णा पाठक अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, उनको भी आयोजकों द्वारा अंग वस्त्र भेंट कर सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं और गणमान्य व्यक्तियों ने मंदिर निर्माण एवं प्राण प्रतिष्ठा जैसे पावन कार्य की सराहना की। पूरे कार्यक्रम के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार,धार्मिक अनुष्ठान और भक्ति संगीत ने वातावरण को पूर्णतः आध्यात्मिक बना दिया। आयोजक मंडल संजय सिंह, संतोष सिंह, नरेंद्र सिंह, जिला पंचायत सदस्य अमन सिंह, सौरभ सिंह, प्रतीक सिंह, अभिषेक सिंह, सत्यम सिंह, आशु सिंह ने बताया कि इस प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और लोगों को अपनी परंपराओं से जोड़ने का कार्य करते हैं। कार्यक्रम के समापन पर सभी अतिथियों और श्रद्धालुओं के प्रति आभार व्यक्त किया गया। बुधवार को हुए कार्यक्रम के मुख्य यजमान हितेश सिंह एवं उनकी धर्मपत्नी अंकित सिंह रही।नवनिर्मित मंदिर प्रांगण में बुधवार को भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्वान पुरोहित पंकज दुबे तथा अजय झा के नेतृत्व में दर्जनों ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार किया।

'प्रदेश में आगामी 25 अप्रैल तक उष्ण लहर लू चलने की सम्भावना'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' प्रदेश में दोपहर के समय 40–50 किमीध्घंटा की गति से चल रही तेज हवाओं के कारण वायुमंडलीय विसरण बढ़ने से अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट के परिणामस्वरूप आज प्रदेश में उष्ण लहर (लू) की स्थिति हरदोई तक सीमित रह गईद्य इसी क्रम में निचले क्षोभ मंडल में आ रही गर्म हवाओं के साथ आतंरिक महाराष्ट्र के आसपास बने प्रतिचक्रवात के प्रभाव से आगामी 25 अप्रैल तक मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहने तथा तापमान में 2–3°C की संभावित बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत प्रदेश में 25 अप्रैल तक उष्ण लहरध्लू चलने की संभावना हैद्य तदुपरांत एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 26 अप्रैल से बादलों की आवाजाही शुरू होने के साथ 27 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बूंदा बांदी के साथ सम्भावित हल्की वर्षा के दृष्टिगत तापमान में 2–3°C की गिरावट के कारण 26 अप्रैल से लू की स्थितियों में सुधार के बावजूद तापमान सामान्य से अधिक बने रहने की संभावना है।

'इच्छुक व्यक्ति, स्वयंसेवी संस्थायें अपनी सेवायें देने हेतु करे आवेदन–संजय कुमार निगम'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' जिला बाल संरक्षण अधिकारीधजिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार निगम ने बताया है, कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत बालकों को सुरक्षित पारिवारिक वातावरण में देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास एवं सामाजिक पुनःएकीकरण कराने हेतु उपयुक्त व्यक्ति, उपयुक्त सुविधा, फास्टर फेयर तथा ग्रुप फास्टर केयर के रूप में जनसामान्य में लोक हितैषी भावना से कार्य करने वाले इच्छुक व्यक्तियों, स्वयंसेवी संस्थाओं से अपनी सेवायें देने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उपयुक्त व्यक्ति तथा उपयुक्त सुविधा की सेवायें निःशुल्क प्रदान की जायेगी। ऐसे व्यक्तिध्संस्थायें जो बालकों को बुनियादी सेवायें उपलब्ध कराने में शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम हों, किसी भी अनैतिक या आपराधिक कार्य में संलिप्त न हों तथा बाल संरक्षण अथवा सामाजिक कार्य करने के क्षेत्र में अनुभवी हों, आवेदन हेतु पात्र होंगे। विस्तृत जानकारी तथा आवेदन का प्रारूप विभागीय वेबसाइटी ttps://mahilakalyan-up-nic-in से डाउनलोड करें अथवा कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारीधजिला बाल संरक्षण इकाई से प्राप्त कर उक्त कार्यालय में जमा करें।

जाम,पार्किंग व्यवस्था,टूटी सड़के,गंदगी जैसी कई समस्याओं से अयोध्या वासी परेशान

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। जाम, पार्किंग समस्या,पानी की पाइव सीवर लाइन जमीन के अंदर डालने के नाम पर अधूरे निर्माण कार्य जैसी प्रमुख समस्या रामनगरी वासियो के लिए बन चुकी है। जिसके चलते इन गंभीर समस्याओं से यहां के लोगों को तो परेशानी हो ही रही है इसके साथ ही साथ राम मंदिर दर्शन पूजन करने आने वाले दूसरे प्रदेश व देश–विदेश के साथ –साथ दुराज से आने वाले श्रद्धालुओं को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसका प्रमुख कारण इस गंभीर समस्या पर अयोध्या नगर निगम लोक निर्माण विभाग जल निगम यातायात विभाग पुलिस विभाग बिजली विभाग सहित अन्य किस्से संबंधित विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी ध्यान नहीं देते नजर आ रहे हैं। बताते चलें जब से राम मंदिर का निर्माण तथा प्राण प्रतिष्ठा हुआ है तब से रामनगरी में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की आवागमन बनी रहती है। शहर का कोई ही ऐसी गली, कालोनी या मोहल्ला ही शायद बचा हो जहां पर यह समस्या ना हो।कोतवाली नगर क्षेत्र के कसाबबाडा, रिकाबगंज,हैदरगंज, वजीरगंज, पुरानी सब्जी मंडी जिला महिला चिकित्सालय, गुरु नानक पब्लिक स्कूल, देवकाली बाईपास, नाका बाईपास, रायबरेली बाईपास मार्ग, चौक, फतेहगंज, रिकाबगंज, नियांवा, गुदरी बाजार सहित अन्य प्रमुख मोहल्ले व कॉलोनी है। इसी तरह की गंभीर समस्या अयोध्या धाम पर भी बनी हुई है।अगर दोनों शहरों में जाम की बात करे तो यह जाम सुबह से लेकर देर शाम तक बनी रहती है। सबसे गंभीर स्थिति खासकर नाका, अयोध्या धाम सहित उस समय जाम की उत्पन्न हो जाती है जब राम मंदिर दर्शन के लिए या अन्य किसी कार्यक्रम में किसी विप व्यक्तियों का मूवमेंट रहता है।जिसके चलते स्कूली बच्चे मरीज, बाहर से आने वाले श्रद्धालु व अन्य राहगीर, दो पहिया व चार पहिया वाहन चालक इस जाम में घंटो फंसे रहते है।परंतु इस गंभीर समस्या पर इससे संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मी ध्यान नहीं दे रहे है।देखा जाये तो इन चौराहों पर आपको एकाद यातायात के सिपाही मिलेंगे।आधा चौराहा आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर ना तो यातायात सिपाही तैनात मिलेंगे और ना ही यातायात ट्रैफिक लाइट से भीड़ को कंट्रोल करते हुए मिलेगी।इस संबंध मे एसपी यातायात अवधेश प्रताप सिंह ने बताया बात कि विभाग में यातायात पुलिस कर्मी पर्याप्त संख्या में है। जो विभिन्न चौराहों पर तैनात रहते हैं।

नवसृजित सीओ सिटी कार्यालय का एसएसपी ने किया लोकार्पण

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या बुधवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने रिकाबगंज स्थित नव सुसज्जित सीओ सिटी कार्यालय का लोकार्पण फीता काटकर किया।लोकार्पण के बाद से सीओ सिटी कार्यालय अब नए रूप में नजर आता दिखाई दिया।वही सीओ सिटी कार्यालय में आने वाले फरियादियो को भी अब बेहतर वातावरण का अनुभव होता दिखा।कर्मचारियों व फरियादियो के बैठने की व्यवस्था को लेकर जहां पर आए फरियादियों ने भी कहा कि अब फरियादियों के लिए भी इंतजार और कार्य निस्तारण की प्रक्रिया पहले की अपेक्षा अधिक सहज हो गई है।जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि रंग–रोगन और साज–सज्जा के बाद कार्यालय का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है, जिससे सरकारी दफ्तर की छवि भी बेहतर हुई है।इस मौके पर पुलिस अधिकारियों ने भी बताया कि समय–समय पर ऐसे सुधार कार्य किए जाते रहेंगे ताकि आमजन को बेहतर सेवाएं मिल सकें। लोकार्पण के समय एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी, सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी,सीओ परिसर योगेंद्र कुमार,सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारीध, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर अश्वनी कुमार पांडे,प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट संजीव कुमार,महिला थाना अध्यक्ष आशा शुक्ला, सहित सभी चौकी के प्रभारी निरीक्षक तथा पुलिस कर्मी मौजूद रहे।

सुपारीः भारतीय संस्कृति की अमिट पहचान - ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश पांडे

भारत में जब भी त्योहारों और शादियों का मौसम आता है, तो पूरा देश रंगों, संगीत और परंपराओं से सराबोर हो जाता है। इन उल्लासपूर्ण आयोजनों के बीच एक छोटी–सी चीज अक्सर अनदेखी रह जाती है दृ सुपारी। यह साधारण–सा बीज वास्तव में भारतीय संस्कृति का एक गहरा प्रतीक है, जो सदियों से हमारे धार्मिक और सामाजिक रीति–रिवाजों में अपनी जगह बनाए हुए है। भारत में सुपारी को पान के पत्ते और चूने के साथ पेश करना सम्मान और सत्कार का प्रतीक माना जाता है। यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि आपसी संबंधों की गहराई और आत्मीयता को दर्शाने वाली परंपरा है। कई समुदायों में इसे मित्रता और विश्वास का प्रतीक माना जाता है, जहां इसे साझा करने से आपसी संबंध और मजबूत होते हैं। ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश पांडे कहते है कि भारतीय शादियों में भी सुपारी का विशेष महत्व है। हिंदू विवाह परंपराओं में 'पान–सुपारी' रस्म के दौरान दूल्हा और दुल्हन सुपारी का आदान–प्रदान करते हैं, जो प्रेम, समृद्धि और अटूट बंधन का प्रतीक होता है। कुछ स्थानों पर नवविवाहित जोड़ा इसे चबाकर अपने रिश्ते को और पक्का करता है। वहीं, शादी में आए मेहमानों को सुपारी बांटना भी शुभ माना जाता है, जो नवविवाहित जोड़े के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाओं का प्रतीक होता है। धार्मिक मान्यताओं में सुपारी को एक पवित्र भेंट माना गया है। विष्णु पुराण में इसका उल्लेख दैवीय अर्पण के रूप में किया गया है और इसे वातावरण शुद्ध करने तथा सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करने वाला माना जाता है। भारत के कई मंदिरों में भक्त इसे देवी–देवताओं को अर्पित करते हैं। पूजा–अर्चना में सुपारी का उपयोग इसे शुभता और धार्मिक आस्था से जोड़ता है। भारत के विभिन्न राज्यों में सुपारी से जुड़ी कई परंपराएँ देखने को मिलती हैं। असम में यह बिहू उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, जहां इसे शुभकामनाओं के रूप में बांटा जाता है। केरल में इसे आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। मिजोरम में सुपारी चबाने की परंपरा पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ निभाई जाती है, जबकि राजस्थान में इसे लोकगीतों और सांस्कृतिक आयोजनों का हिस्सा बनाया जाता है। समाज में लोगों को जोड़ने और आपसी संबंधों को मजबूत करने में सुपारी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। खासकर भारत के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में यह एक सामाजिक गतिविधि के रूप में देखी जाती है। पुराने समय में लोग समूहों में बैठकर सुपारी चबाते हुए कहानियाँ सुनाते, समाचार साझा करते और अपने रिश्तों को गहरा करते थे। भारत के अलग–अलग हिस्सों में सुपारी चबाने की शैली भी अलग होती है। कहीं इसे विशिष्ट आकृतियों में काटा जाता है, तो कहीं इसे एक खास अंदाज में लपेटा जाता है। इसकी मीठी, तीखी और ठंडी अनुभूति इसे एक अनूठा स्वाद देती है, जिसे सदियों से सराहा गया है। सुपारी केवल एक बीज नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा, सम्मान और रिश्तों की गहराई का प्रतीक है। यह वह कड़ी है जो अतीत से वर्तमान को जोड़ती है। जब हम अपनी समृद्ध परंपराओं की बात करते हैं, तो हमें इस साधारण–सी सुपारी को नहीं भूलना चाहिए, जिसने हमारी संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

रोटरी द्वारा विश्व पृथ्वी दिवस पर जागरूकता रैली, बच्चों ने दिया हरित भविष्य का प्रेरक संदेश

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर रोटरी डिस्ट्रिक 3120 के निर्देशन में रोटरी क्लब जौनपुर एवं ब्लॉसम स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में एक प्रेरणादायी जन–जागरूकता अभियान के तहत रैली का आयोजित किया गया। यह अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी को समझने का एक सशक्त प्रयास बना। रोटरी क्लब ने बच्चों और समाज के लोगों को यह संदेश दिया गया कि धरती हमारी माता है और इसकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। हर व्यक्ति का छोटा प्रयास मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकता है। यह आयोजन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हुआ। सभी ने संकल्प लिया कि वे धरती को स्वच्छ और हरित बनाने में योगदान देंगे। संयोजक शम्स अब्बास और पंकज जायसवाल ने प्रार्थना सभा में बच्चों को प्रकृति संरक्षण की शपथ दिलाई। ब्लॉसम स्कूल के बच्चों द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली पूरे क्षेत्र में उत्साह और ऊर्जा का संचार करती रही। "धरती को हरा–भरा बनाएं" और "पेड़ लगाएं, प्रकृति बचाएं" जैसे नारों से वातावरण गूंज उठा। यह रैली केवल नारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि हर बच्चे के मन में प्रकृति के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी का भाव भी जागृत करने का प्रयास है। बच्चों ने यह संदेश दिया कि बदलाव की शुरुआत खुद से करनी होगी। उनके जोश और उत्साह ने सभी को प्रेरित किया कि वे भी पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाएं। यह रैली एक नई सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतीक बनी। सुबह 7:30 बजे आरंभ हुई इस रैली में लगभग 150 बच्चों ने भाग लिया और पूरे मार्ग में जागरूकता फैलायी। रैली का शुभारंभ पर्यावरण को–चेयरमैन रविकांत जायसवाल और पूर्व अध्यक्ष कृष्ण कुमार मिश्र द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। उन्होंने बच्चों को तेज धूप से बचने के साथ–साथ प्रकृति की सुरक्षा के लिए जरूरी उपायों के बारे में भी बताया। यह संदेश दिया गया कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बच्चों को यह समझाया गया कि आज की छोटी लापरवाही भविष्य के लिए बड़ा संकट बन सकती है। इसलिए अभी से सतर्क रहना जरूरी है। रविकांत जायसवाल ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि "आपका एक छोटा प्रयास, धरती के लिए बड़ा उपहार है।" उन्होंने स्वच्छता, प्लास्टिक मुक्त जीवन, वर्षा जल संचयन और ग्रीन मूवमेंट जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया। यह संदेश दिया गया कि अगर हम अपने दैनिक जीवन में छोटे–छोटे बदलाव करें, तो पर्यावरण को काफी हद तक सुरक्षित किया जा सकता है। बच्चों ने भी इन बातों को गंभीरता से समझा और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। यह कार्यक्रम जागरूकता के साथ–साथ जिम्मेदारी का भी पाठ सिखाने वाला रहा। रोटरी अध्यक्ष विवेक कुमार सेठी ने कहा कि हमें आज ही कदम उठाने होंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और सुंदर धरती मिल सके। क्लब सचिव डॉ. बृजेश कन्नौजिया ने प्लास्टिक के उपयोग को छोड़ने और सफाई पर विशेष ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल एक आदत नहीं बल्कि एक संस्कार होना चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। निर्वतमान अध्यक्ष श्याम वर्मा और शिवांशु श्रीवास्तव ने स्कूल के अध्यापकों के साथ बच्चों की रैली का संचालन किया। कार्यक्रम के अंत में संदीप सेठ (जफराबाद) ने कहा इस अवसर ने यह साबित कर दिया कि जब समाज के लोग एकजुट होते हैं तो बदलाव संभव है। यह आयोजन केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सतत आंदोलन की शुरुआत है। हर व्यक्ति यदि अपनी जिम्मेदारी समझे तो धरती को फिर से हरा–भरा और सुंदर बनाया जा सकता है। इस अवसर पर संजय जायसवाल, मनीष गुप्ता सहित ब्लॉसम स्कूल के शिक्षकगण उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे।

स्कूल चलो अभियान रैली और गोष्ठी का आयोजन

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।दिशा संस्था के तत्वावधान मे स्कूल चलो अभियान रैली और गोष्ठी कम्पॉजिट विद्यालय पिपरी मसौधा मे सम्पन्न हुआ।इस मौके पर आंगनवाड़ी के सहयोग से स्कूल चलो अभियान और गोष्ठी का आयोजन किया गया।रैली में ब्लॉक कोडीनेटर राजा राम जी द्वारा बच्चों से प्रेरक नारे लगाए गए।जिनमें प्रमुख रूप से शिक्षा है।रैली का संचालन यूनिसेफ के पूर्व प्रतिनिधि धीरेन्द्र नाथ पाण्डेय दिशा संस्था से सुगम कर्ता मीरा द्वारा किया गया। इस मौके पर कम्पॉजिट

विद्यालय पिपरी मे नोडल टीचर नन्द माधव त्रिपाठी सहायक टीचर अमित श्रीवास्तव, रुपम शुक्ला,प्रतिमा तिवारी,शालिनी सिंह,प्रतिमा रावत, सपना सिंह.शिक्षा मित्र गीता वर्मा साहिन अन्जुम मौजूद रही।

नवागत डीएम शशांक त्रिपाठी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद पत्रकार वार्ता में गिनाई अपनी प्राथमिकता

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या।रामनगरी में दर्शन–पूजन के उपरांत नवागत जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बुधवार को कोषागार कार्यालय पहुंचकर विधिवत अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद पत्रकार वार्ता में उन्होंने अपनी प्रमुख प्राथमिकता भी गिनाई सबसे पहले उनके कार्यभार ग्रहण करने से पहले उन्हें पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिससे पूरे कार्यक्रम का माहौल गरिमामय हो उठा।कार्यभार ग्रहण करते ही प्रशासनिक महकमे में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार देखा गया।जिलाधिकारी के स्वागत के लिए अयोध्या के विभिन्न विभागों के अधिकारी पहले से ही कोषागार कार्यालय में मौजूद थे।अधिकारियों ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया और उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं।इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण देखने को मिला।शशांक त्रिपाठी ने कार्यभार संभालने के बाद अधिकारियों से संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया और जिले की वर्तमान स्थिति एवं प्रमुख योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने संकेत दिया कि शासन की प्राथमिकताओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।साथ ही उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। पत्रकारों से खटीक होते हुए उन्होंने अपनी कार्ययोजना और प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिया।कार्यभार ग्रहण के इस अवसर पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए थे।पूरे कार्यक्रम को सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया गया।कुल मिलाकर, नवागत जिलाधिकारी का आगमन जिले के प्रशासनिक ढांचे के लिए एक नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। पत्रकारों से मुलाकात के दौरान उन्होंने अपनी प्राथमिकता गिनाई।उन्होंने कहा कि रामनगरी में हो रहे योजनाओं को पूरा करना उनकी प्राथमिकता है साथ ही साथ राम मंदिर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों पर दर्शन पूजन करने आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कठिनाई न हो इसके लिए उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा जिसको लेकर एक कार्य योजना भी बनाई जाएगी बताया कि अयोध्या जनपद के चहुँमुखी को विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शासन के मंसानुरुप फरियादियों के समस्याओं का शीघ्र से शीघ्र समाधान करना उनकी प्राथमिकताओं में से एक है साथ ही साथ शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाना भी अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक बताया।

गौवंश के संरक्षण में उत्तर प्रदेश सरकार की संवेदनशील पहल उपाध्यक्ष - महेश शुक्ला

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या । उपाध्यक्ष गोसेवा आयोग महेश शुक्ल व सदस्य गोसेवा आयोग दीपक गोयल की अध्यक्षता में सर्किट हाऊस सभागार जनपद स्तरीय गो संरक्षण एवं अनुश्रवण समिति की समीक्षा बैठक हुई।इस मौके पर उपाध्यक्ष ने संबंधित विभागों की बिन्दुवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को फटकार भी लगाई।निर्देश दिया कि गोवंशों के संरक्षण के लिए जो भी शासन के निर्देश दिए गए है।उनको धरातल पर लागू किया जाए।इस मौके पर उन्होंने डीसी मनरेगा को निर्देश दिया कि चारागाह क्षेत्र का विकास कराया जाए।सिंचाई विभाग को तालाबों में पर्याप्त जल उपलब्ध कराने को निर्देश दिया। सभी उप जिलाधिकारी से गोचर भूमि को चिन्हित कर शीघ्र उसे विकसित कराने के निर्देश दिए।उपाध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दूरदर्शी एवं कुशल नेतृत्व में उ०प्र० सरकार गौ सेवा को केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं बल्कि मानवीय सामाजिक एवं आध्यात्मिक उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार करते हुए सतत कार्य कर रही है। राज्य सरकार द्वारा निराश्रित एवं असहाय गौवंश के संरक्षण संवर्धन एवं समुचित देखभाल के लिए व्यापक एवं यह आयामी योजनाएं संचालित की जा रही है, जिनके सकारात्मक परिणाम प्रदेशभर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे है। उत्तर प्रदेश दश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ निराश्रित गौवंश के भरण–पोषण के लिए सरकार द्वारा 50 रुपये की दर से भरण–पोषण की धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है।प्रदेश सरकार की महत्त्वाकांक्षी गौ–संरक्षण नीति के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य के विभिन्न जनपदों में 7,700 से अधिक गौ–आश्रय स्थल सक्रिय रूप से संचालित हो रहे है। इन आश्रय स्थलों में 16 लाख से अधिक निराश्रित गौवंश को सुरक्षित आवास, नियमित आहार, स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। यह व्यवस्था न केवल गौवंश के संरक्षण को सुनिश्चित कर रही है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था एंव सामाजिक संतुलन को भी सुदृढ़ कर रही है। गौशालाओं के प्रभावी संचालन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 5.446 गोशालाओं में 7,592 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गये है। अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली 24□7 कार्यरत रहकर गोवंश की सुरक्षा, देखभाल की गुणवत्ता तथा प्रशासनिक जवाबदेही कर रही है। मा० मुख्यमंत्री जी निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के माध्यम से सरकार ने गौ–संरक्षण को जन आंदोलन का रूप प्रदान किया है।इस योजना के अन्तर्गत अब तक 1,67,065 गौवंश इच्छुक एव जिम्मेदार गौपालकों को सुपुर्द किए गये है।सरकार द्वारा प्रत्येक गौवंश के लिए 50 रुपये प्रतिदिन की दर से पोषण भत्ता सीधे गौपालकों के बैंक खातों में डीवीटी के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। यह पहल न केवल गौवंश के संरक्षण में सहायक है, बल्कि गौपालकों की आय वृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।जनपद अयोध्या में जिला प्रशासन द्वारा गौ संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में जनपद में 97 गौ–आश्रय स्थल क्रियाशील है, जिनमें 12,433 गौवंश का संरक्षण एंव पालन–पोषण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 1441 प्रगतिशील गौपालकों ने सहभागिता योजना के अन्तर्गत 2571 गौवंश को अपनाकर सामुदायिक सहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार उ०प्र० गोवध निवारण अधिनियम 1955 के अन्तर्गत गौवंश के सुरक्षा के प्रति पूर्णत प्रतिबद्ध है। जीरो टॉलरेंस नीतिः गौवंश संरक्षण से सम्बन्धित नियमों के उल्लंघन पर त्वरित एवं कठोर दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। कुछ असामाजिक एवं निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार का खण्डन करते हुए उपाध्यक्ष गो सेवा आयोग महेश शुक्ल ने बताया कि गौ सेवा के पदाधिकारियों के द्वारा गौ–आश्रय स्थलों का नियमित भ्रमण करते हुए निरन्तर पैनी निगाह रखी जा रही है और कोई भी अनियमितता प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि निराश्रित गौवंश की सेवा एंव संरक्षण के लिए कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।राज्य सरकार गौवंश के प्रति अपनी संवेदनशीलता मानवीय एवं समर्पित दृष्टि के साथ सुशासन के सिद्धांतों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह, अपर निदेशक ग्रेड–2 अयोध्या मंडल डॉ ए के वैस, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ इंद्र देव माहर उपस्थित रहे।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।